

[2023] 4 एस. सी. आर 1118

/

[2023] 4 एस सी आर।

/

आंध्र प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. v.

वरला रामैया ई. टी. सी.

(सिविल अपील संख्या 2022 की 8540-8541) 03 मई, 2023

/

[न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश, जेजे।]

सरकारी आदेश: गलत व्याख्या-उच्च न्यायालय ने जी. ओ. के अनुसार आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी-तथ्यों के आधार पर, जी. ओ. के आधार पर, राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक कैबिनेट उप-समिति नियुक्त की-सी. बी. आई./सी. आई. डी./लोकायुक्ता को जांच सौंपने का प्रस्ताव-दूसरे जी. ओ. के आधार पर, राज्य ने इन आरोपों की जांच करने के लिए एस. आई. टी. का गठन किया-इसके बाद एस. आई. टी. के पत्र के आधार पर, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मामले को सी. बी. आई. को भेजने का अनुरोध किया-जी. ओ. को चुनौती देने वाली लिखित याचिकाएं-भारत संघ और प्रवर्तन निदेशालय को शामिल करने के लिए राज्य द्वारा आवेदन, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया-इसके बाद, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने जी. ओ. की गलत व्याख्या की-जी. ओ. को पिछली सरकार द्वारा लिए गए पहले के फैसलों को पलटने और/या पिछली सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है-पिछली सरकार के भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों की जांच के लिए उप-समिति और एस. आई. टी. का गठन किया गया है-उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया कि अपीलकर्ता ने केंद्र सरकार से मामले को सी. बी. आई. को भेजने का अनुरोध किया था, जिसके बाद सहमति दी गई थी-उच्च न्यायालय को अंतरिम रोक नहीं देनी चाहिए थी-मामला समय से पहले शुरू होने वाले चरण में है-साथ ही भारत संघ एक उचित और आवश्यक पक्ष है जिसे रिट याचिकाओं में प्रतिवादी के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए-उच्च न्यायालय रिट का निपटारा करने के लिए।

/

/

/

/

/

सिविल अपीलिय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 8540-8541।

2020 के आई. ए. संख्या 1 में अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के 2020 के डब्ल्यू. पी. संख्या 6562 और 6711 में दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

/

1118

1119

आंध्र प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. v. वरला रामैया ई. टी. सी.

/

एस. निरंजन रेड्डी, वरिष्ठ अधिवक्ता, महफूज ए. नाज़की, पोलांकी गौतम, शेख मोहम्मद हनीफ, टी. विजय भास्कर रेड्डी, के. वी. गिरीश चौधरी, सुश्री राजेश्वरी मुखर्जी, सुश्री नीति रिचरिया, साहिल रवीन, सुश्री मुक्ति सिंह, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री प्रेरणा सिंह, गुंटूर प्रभाकर, गुंटूर प्रमोद कुमार, सुघोश सुब्रमण्यम, अग्रिश आदित्य, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. 2020 की रिट याचिका और 2020 की रिट याचिका में आई. ए. No.1/2020 में अमरावती में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित अंतरिम आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए जी. ओ. आर. टी. No.1411 दिनांक 26.06.2019 और जी. ओ. आर. टी. No.344 दिनांक 21.02.2020 के अनुसार आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी है, आंध्र प्रदेश राज्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

/

/

2. संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं: 2.1 आई. डी. 1 पर जारी जी. ओ. के आधार पर राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक मंत्रिमंडल उप-समिति नियुक्त की। 27.12.2019 पर, कैबिनेट

उप-समिति ने कुछ आरोपों के बारे में प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज करते हुए एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।आई. डी. 1 पर आयोजित बैठक के दौरान, उप-समिति ने जांच को सी. बी. आई./सी. आई. डी./लोकायुक्ता को सौंपने पर विचार करने का भी संकल्प लिया।रिपोर्ट के आधार पर, दूसरे जी. ओ. दिनांक 21.02.2020 के अनुसार, राज्य ने इन आरोपों की जांच करने के लिए एस. आई. टी. का गठन किया।उक्त निर्णय को 04.03.2020 पर आयोजित अपनी बैठक के दौरान मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।इसके बाद एस. आई. टी. के प्रमुख ने सरकार को आई. डी. 1 पर लिखा कि इस मामले के व्यापक प्रभाव हैं और इसलिए इसे सी. बी. आई. जैसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की आवश्यकता है। तदनुसार, 23.03.2020 दिनांकित पत्र के माध्यम से राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मामले को सी. बी. आई. को भेजने का अनुरोध किया। आई. डी. 1 पर, राज्य ने आंध्र प्रदेश राज्य के भीतर दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा शक्तियों के प्रयोग के लिए स्पष्ट रूप से अपनी सहमति दी, ताकि सी. बी. आई. आंध्र प्रदेश राज्य फाइबर नेट लिमिटेड से जुड़े घोटाले के संबंध में ऐसी जांच कर सके।

/

/

/

/

1120

/

[2023] 4 एस सी आर।

/

2.2 उस स्तर पर, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने 2020 की वर्तमान रिट याचिका No.6562 और 2020 की रिट याचिका No.6711 के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष जी. ओ. दिनांकित 26.06.2019 और बाद के जी. ओ. दिनांकित 21.02.2020 दोनों को चुनौती दी।राज्य ने भारत संघ और प्रवर्तन निदेशालय को आरोपित करने के लिए आवेदन दायर किए, क्योंकि वह इन आरोपों की केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच कराना चाहता था।उच्च न्यायालय ने अभियोग लगाने की याचिकाओं को खारिज कर दिया।हालाँकि, इसके बाद आक्षेपित अंतरिम आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उपरोक्त दो जी. ओ. के अनुसार आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इसलिए, वर्तमान अपीलें।

/

3. आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. निरंजन रेड्डी ने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर संबंधित जी. ओ. की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है:

/

"1. विधि का शासन निरंतरता की मांग करता है और एक नई सरकार को पिछली सरकार के फैसलों को पलटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

/

2. कि सरकार के पास अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए समीक्षा की 'अंतर्निहित' शक्ति नहीं है।

3. कि 'कोई कमी या कमी' नहीं थी जिसे भरने की आवश्यकता थी और इसलिए वह राज्य अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था।

/

4. वह शिकायतकर्ता और अन्वेषक एक ही होने के कारण पक्षपात की संभावना है;

5. आयोग/एस. आई. टी. के गठन की शक्तियों का उपयोग अदालतों द्वारा भी संयम से किया जाना चाहिए। इसलिए, उक्त प्रतिबंध सरकार पर और भी अधिक जोश के साथ लागू होता है। "

/

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त सभी आधार पूरी तरह से अस्थिर हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की उचित रूप से सराहना नहीं की है कि प्रश्न यह नहीं था कि क्या पिछली सरकार की नीतियों को जारी रखा जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रश्न यह था कि क्या पिछली सरकार के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार/कदाचार के कृत्यों की जांच की जानी चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की ठीक से सराहना नहीं की है कि भ्रष्टाचार के व्यापक आरोप थे और इस प्रकार, आरोप ए थे

/

/

1121

आंध्र प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. v. वरला रामैया ई. टी. सी. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

जांच की आवश्यकता थी और इसलिए, तदनुसार भ्रष्टाचार/कदाचार के कृत्यों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था और कोई अन्य दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था।

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने उचित रूप से इस बात की सराहना नहीं की है कि संबंधित जी. ओ. राज्य सरकार द्वारा अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए थे और इस तरह पिछली सरकार द्वारा लिए गए पहले के निर्णयों की समीक्षा नहीं की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच करने के कार्य को उस अर्थ में 'समीक्षा' नहीं कहा जा सकता है जिसमें उच्च न्यायालय ने समझा है।

/

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की उचित रूप से सराहना नहीं की है कि जी. ओ. के अनुसार एस. आई. टी. के गठन को केवल पिछली सरकार के खिलाफ कथित कुकर्मों/भ्रष्टाचार/कदाचार के कृत्यों की जांच करने के लिए तथ्य माना जा सकता है। 3.4 अपीलार्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा संबंधित जी. ओ. के गुण-दोष और उप-समिति/एस. आई. टी. के दायरे और दायरे के आधार पर कई अन्य प्रस्तुतियाँ की गई हैं।

/

/

3.5 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से कार्य नहीं किया जैसा कि उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में राज्य ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा आरोपों की जांच कराने का प्रस्ताव किया था, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया था ताकि मामले को सी. बी. आई. को भेजा जा सके। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इसलिए, कोई अंतर्निहित पूर्वाग्रह नहीं था। 4. मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध किया जाता है। मूल रिट याचिकाकर्ताओं-उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे द्वारा गुण-दोष के आधार पर कई प्रस्तुतियाँ की गई हैं।

/

/

4.1 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपील उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश/रोक के खिलाफ हैं और मुख्य रिट याचिकाओं पर अभी तक उच्च न्यायालय द्वारा विचार, निर्णय और निपटान नहीं किया गया है।

/

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रोक 2 साल से अधिक समय से जारी है और इसलिए, यह न्यायालय मामले के गुण-दोष की जांच नहीं कर सकता है और

लंबित रिट याचिकाओं में मामले के गुण-दोष को उच्च न्यायालय द्वारा तय करने के लिए छोड़ सकता है।

/

1122

/

[2023] 4 एस सी आर।

5. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुनने के बाद और दिनांकित जी. ओ. 1 और जी. ओ. 2 के अनुसरण में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क पर विचार करने के बाद, हमारी प्रथम दृष्टया राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त दो जी. ओ. के अनुसरण में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए दिए गए कुछ तर्क स्पष्ट नहीं हो सकते हैं, विशेष रूप से जब उच्च न्यायालय ने कहा है कि नई सरकार को पिछली सरकार के निर्णयों को पलटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

/

5.1 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह कहना उचित है कि उच्च न्यायालय ने उपरोक्त दो जी. ओ. की गलत व्याख्या की है और/या गलत अर्थ निकाला है और इसे पिछली सरकार के निर्णयों को पलटने के समान माना है। यदि उपरोक्त दो जी. ओ. पर विचार किया जाता है, तो यह देखा जा सकता है कि इसे पिछली सरकार द्वारा लिए गए पहले के निर्णयों को पलटने और/या पिछली सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। पिछली सरकार के भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों की जांच के लिए उप-समिति और एस. आई. टी. का गठन किया गया है।

/

/

5.2 तथापि, कुछ अन्य पहलू हो सकते हैं जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा लंबित रिट याचिकाओं में, विशेष रूप से समिति के निर्देश की शर्तों के संबंध में विचार करने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने कानूनी पहलुओं पर इस न्यायालय के फैसलों के आधार पर हमारे समक्ष उठाए गए विभिन्न तर्कों पर भी विचार नहीं किया है। इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया है कि पहले याचिकाकर्ता (अब अपीलकर्ता) ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि मामले को सीबीआई को भेजने के लिए दिनांकित पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया था, जिसके बाद 13.07.2020 पर दी गई सहमति को ध्यान में रखा गया है।

/

/

5.3 हमारे विचार में, उच्च न्यायालय को अंतरिम रोक नहीं देनी चाहिए थी जब इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पूरा मामला समय से पहले शुरू होने वाले चरण में है। केंद्र सरकार ने अभी तक पहले याचिकाकर्ता (अब अपीलार्थी) द्वारा दिए गए पत्र और सहमति पर कोई निर्णय नहीं लिया है। बेहतर होता कि उच्च न्यायालय पक्षकारों को दलीलें पूरी करने की अनुमति देता और उसके बाद अपने समक्ष पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान करके किसी न किसी तरह से रिट याचिकाओं का फैसला करता।

/

5.4 यह भी हमारे संज्ञान में लाया गया है कि याचिकाकर्ताओं (अब अपीलकर्ता) ने भारत संघ और ए को शामिल करने के लिए एक आवेदन दायर किया था।

/

1123

आंध्र प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. v. वरला रामैया ई. टी. सी. [एम. आर. शाह, जे.]

प्रवर्तन निदेशालय। उपरोक्त आवेदन को अन्य बातों के साथ-साथ एक अलग आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावित उत्तरदाताओं की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी। उच्च न्यायालय का उअंतर्गत ोक्त दृष्टिकोण, विशेष रूप से जब मुख्य रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाना बाकी है, और याचिकाकर्ताओं (अब अपीलकर्ताओं) द्वारा किए गए अनुरोध अंतर्गत विचार किया जा रहा है, तो इसे अपनाया नहीं जाना चाहिए था। शायद, उत्तरदाता/रिट याचिकाकर्ता स्वयं भारत संघ को रिट याचिकाओं में एक पक्षकार बना सकते थे क्योंकि याचिकाकर्ता (अब अपीलार्थी) के दिनांक 23.03.2020 के पत्र पर निर्णय का उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका पर प्रभाव पड़ता। हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि भारत संघ एक उचित और आवश्यक पक्ष है जिसे रिट याचिकाओं में प्रतिवादी के रूप में रखा जाना चाहिए।

/

/

6. उपरोक्त कारणों से, हम यह स्पष्ट करते हुए कि हमने मामले के गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है, आई. ए. 1/2020 और आई. ए. 2/2020 में दिनांकित 16.09.2020 आदेशों को दरकिनार करने के लिए इच्छुक हैं। उच्च न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह हमारे आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, गुण-दोष और विधि के अनुसार रिट याचिकाओं का निर्णय और निपटान करेगा। तथ्यों और विधि को नियंत्रित करने वाले मुद्दों पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने की

अवधि के भीतर अंततः रिट याचिकाओं का निपटारा करने का प्रयास कर सकता है। प्रस्तावित प्रत्यर्थी अर्थात् 2020 के आई. ए. 2 में भारत संघ, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, को रिट याचिकाओं में प्रत्यर्थी के रूप में जोड़ने का निर्देश दिया जाता है और उसके विचारों पर ध्यान देना होगा।

/

/

7. अपीलों की अनुज्ञात जाती है। विविध अनुप्रयोग बंद हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

/

निधि जैन

अपीलों की अनुज्ञात गई।

(सहायक: राखी, एलसीआरए)

/

/